(d) the action taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) The Cantonment Boards are local authorities with statutory powers and responsibilities and are allowed to function as such within the ambit of the Cantonments Act. While no formal assessment of the working of each Cantonment Board is made by Government, a general watch is kept over their working and any deficiencies coming to notice are looked into.

(b) to (d). Do not arise.

नागालैंड के विषय को गृह मन्त्रालय को हस्तांतरित करना

*530. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**

श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 मई, 1969 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई प्रधान मन्त्री की यह घोषणा सही है कि सरकार भविष्य में विद्रोही नागाओं के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी तथा नागालैंड की समस्याएं नगालैंड के राज्यपाल और सरकार द्वारा स्वयं हल की जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में नागालैंड की निश्चित समस्याएं अन्य राज्यों की समस्याओं की तरह गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा हल की जायेंगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 16 मई, 1969 को विरोधी पक्ष के संसद सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक में प्रधान मन्त्री ने बताया बताया था कि नागा समस्या का समाधान 1960 में ही हो गया था और भारत के सभी नागरिक, जिनमें नागा शामिल है, नागालैंड की बेहतरी के विषय में नागालैंड की सरकार और वहां के राज्यपाल को सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन छिपे नागाओं के साथ बातचीत करने का भारत सरकार का कोई विचार नहीं है ।

(ख) इस बारे में पहले भी कई बार सदन को विस्तार से स्थिति बताई जा चुकी है । भारत सरकार के जिस मन्त्रालय से जिस मामले का संबंध होता है, उस पर नागालैंड की सरकार उस मन्त्रालय से सीधे ही सम्पर्क स्थापित कर लेती है । विदेश मन्त्रालय नागालैंड की राजनैतिक स्थिति पर कार्यवाई करती है । जैसा कि सदन को मालूम है, यह प्रबन्ध 1960 में नागा नेताओं से हुई सहमती के आधार पर हुआ है ।

Right to Work and Livelihood

*531. SHRI LOBO PRABHU : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the minimum livelihood, envisaged in in the Draft Fourth Plan and the calculation of the corresponding national product considering the statements of the right to livelihood and work ;

(b) since the second poorest decile of the population is estimated to have at the end of the draft plan period a consumption level of Rs. 15 in terms of 1960-61 prices, what will be the annual cost of ensuring the existing minimum wage to adult section of this population through general extension of the standing offer of employment contemplated in the draft only for selected areas ;

(c) the reasons why the cost of creating employment opportunities is not sought to be reduced through offer of loans and grants to the private sector ;

(d) the reasons why particularly rural housing is not accepted for loans and grants in view of its potentials for activating many industries and engaging all kinds of labour ; and

(e) the reasons why the final plan should not make provision of loans and grants for rural housing ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) and (b). It is not clear what the Hon'ble Member means by "minimum livelihood". Presumably he has in mind the concept of a minimum income or minimum consumption needs. The estimated consumption of second